नईदुनिया

संपादकीय

नशा तस्करों का गढ़ बनता गुजरात

भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात ने हमारे देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और स्वामी दयानंद जैसी महान विभूतियां दी हैं। महात्मा गांधी देश को स्वतंत्रता दिलाने के अलावा शराब जैसी बुराई पर रोक लगाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। समाज पर पड़ने वाले शराब के दुष्प्रभावों को देखते हुए ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पराधीनता के युग में यह घोषणा की थी कि यदि भारत का शासन आधे घंटे के लिए भी उनके हाथ में आ जाए तो वह शराब की सभी डिस्टिलरियों और दुकानों को बिना मुआवजा दिए ही बंद कर देंगे। यही नहीं, गांधी जी ने महिलाओं को भी स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा और देश के कोने-कोने में महिलाओं ने छोटे दूध पीते बच्चों तक को गोद में लेकर शराबबंदी की मांग के साथ-साथ विदेशी कपड़ों की होली जलाई और अनेक महिलाओं ने 2-2, 3-3 वर्ष की कैद भी काटी थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की स्वतंत्रता और रियासतों का भारत में विलय करवाने का श्रेय प्राप्त है जबकि स्वामी दयानंद ने 'आर्य समाज' की स्थापना करके देश में जन जागृति की एक नई लहर चलाई। ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाले राज्य में आज भारी मात्रा में नशा पकड़ा जा रहा है। गुजरात जिसे 'ड्राई स्टेट' कहा जाता है, अब 'पाऊडर स्टेट' बनता जा रहा है तथा मात्र गत 4 वर्षों में ही यहां लगभग 32,813 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। राज्य में मात्र वर्ष 2024 में ही 4,862 किलो नशीले पदार्थ जब्त किए गए। ये आंकड़े सिर्फ बरामदगी के हैं, जबकि इसके अलावा न जाने कितना नशा बिना पकड़े निकल गया होगा। इससे स्पष्ट है कि राज्य में नशीले पदार्थों का कारोबार कितनी तेजी से फैल रहा है।

फरवरी, 2024 में नौसेना तथा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' की टीम ने 1300 से 2000 करोड़ रुपए मूल्य की 3300 किलो ड्रग्स जब्त की थी।

अप्रैल, 2024 में भारतीय तटरक्षकों ने पोरबंदर के निकट 6000 करोड़ रुपए मूल्य की 86 किलो ड्रग्स पकड़ी।

15 नवम्बर, 2024 को पोरबंदर तट के निकट भारतीय जल क्षेत्र में 'नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' (एन.सी.बी.), भारतीय नौसेना तथा गुजरात पुलिस की 'एंटी टैररिस्ट स्क्वाड' (ए.टी.एस.) टीमों ने एक संयुक्त अभियान में 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करके एक नाव में से 700 किलो 'मेथामफेटामाइन' नामक नशीला पदार्थ जब्त किया जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2500 से 3500 करोड़ रुपए के बीच बताई गई। उल्लेखनीय है कि गुजरात तट बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप लाने के लिए एक विशेष 'एंट्री प्वाइंट' के रूप में उभरा है तथा वर्ष 2024 में समुद्री मार्ग से नशा तस्करी के मामले में कुल 25 विदेशी गिरफ्तार किए गए जिनमें 11 ईरानी और 14 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं जो सभी अभी जेल में हैं।

गुजरात में नशीले पदार्थों की बरामदगी की नवीनतम कड़ी में 12-13 अप्रैल, 2025 की दरम्यानी रात को भारतीय तट रक्षकों ने पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में एक 'स्पीड बोट' से 1800 करोड़ रुपए मूल्य के 300 किलो नशीले पदार्थ जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। अपने कार्यों से विश्व के समक्ष नए आदर्श प्रस्तुत करने वाले महापुरुषों के राज्य गुजरात में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी से स्पष्ट है कि आज यह राज्य नशा तस्करों का स्वर्ग बनता जा रहा है जिससे इसकी बदनामी भी हो रही है। अतः कठोरतम कदम उठाकर इस बुराई को समाप्त करने की जरूरत है।

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़काई गई सुनियोजित हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं?

कमलेश पाण्डेय

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई वह सुनियोजित थी। यह अब तक की केन्द्रीय एजेंसियों की तफ्तीश से काफी कुछ साफ होता जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इस सुनियोजित हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? राज्य प्रशासन की जवाबदेही क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? उसकी लापरवाही पर संसद और जिम्मेदार संस्थाएं कब तक एक्शन लेंगीं, क्योंकि विदेशी-देशी सांठगांठ से हुई हिंसा में हिंदुओं के जानमाल की क्षति हुई है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। इसलिए उदंड और बेलगाम राजनीति की लगाम कौन कसेगा, यह अब यक्ष प्रश्न है?

जांच एजेंसियों के सूत्रों की मानें तो इस हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। लगभग पिछले तीन महीनों से इलाके के लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पूरे मामले की जांच के दौरान पाया गया है कि यह आतंकवाद फैलाने का नया तरीका है। प्रारंभ में रामनवमी की तारीख तय थी, लेकिन उस दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं लेकिन वक्फ संशोधन कानून ने ट्रिगर पॉइंट दे दिया।

खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद की हिंसा में विदेशी हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता है। जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) जैसे समूह बांग्लादेश बॉर्डर से लगते इलाकों और सुंदरबन डेल्टा में हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। ये आतंकी संगठन ट्रेनिंग देने के साथ ही प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन अशांति को बढ़ाने के लिए वैश्विक मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। वे दहशत फैलाने के लिए अफ़वाह फैलाने में मदद कर रहे हैं। यह उसी तरह है जैसे सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता छीनने के रूप में प्रचारित किया गया था। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए लोगों को भी नायक के रूप में महिमामंडित किया जा रहा है।

दरअसल वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़क उठी है, उससे खुफिया एजेंसियों ने अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाओं की आशंका जताई है। इसके दृष्टिगत देशभर में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। यह बात दीगर है कि अभी तक अन्य राज्यों से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की अधिसूचना के मद्देनजर अभी तक अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी सांप्रदायिक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है। फिर भी पहले मुस्लिम आक्रान्ताओं ने और फिर ब्रिटिश नौकरशाहों ने अपने-अपने प्रशासनिक स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी-ऐसी अव्यवहारिक नीतियों को कानूनी अमली जामा पहनाया, जिससे हिन्दू समाज जाति और क्षेत्र के नाम पर बिखर गया। कभी मुस्लिम अधिकारी तो कभी ईसाई अधिकारी और उनके पिट्ठू लोग हिन्दुओं पर हावी होते चले गए। इसी कड़ी में सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय हिंसा को अघोषित प्रशासनिक एजेंडे के तौर पर बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा कभी प्रशासनिक उदासीनता तो कभी पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाते हुए संगठित अपराध को बढ़ावा दिया गया, जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली गई।

इसी स्थिति से निजात पाने के लिए देश में आजादी की लड़ाई तेज हुई और साम्पदायिक विभाजन तक की नौबत आई। इस दौरान हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी खूब हुए। कथित राष्ट्रवादियों ने ढोंगी धर्मनिरपेक्षता की तो खूब बातें कीं, लेकिन अपने कुत्सित जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक एजेंडे से आगे की कभी नहीं सोच पाए। मसलन बहुमत की आड़ में शांतिप्रिय सत्ता परिवर्तन भी सुनिश्चित हुआ, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका और अन्य समाज के जिम्मेदार स्तंभों से जुड़े लोग मुगलिया और ब्रितानी प्रशासनिक लापरवाहियों से कोई सबक नहीं सीख पाए। वह लोग अपने फायदे की बात तो करते रहे, लेकिन, लेकिन आमलोगों के सुख-शांति में खलल डालने वालों के खिलाफ कभी सख्ती नहीं दिखाई। इस नजरिए से संसद और विधान मंडलों ने प्रभावकारी कानून नहीं बनाए। परिणाम यह है कि आज भी आम आदमी सुपोषण योग्य भोजन, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा, जन-सुरक्षा के लिए मोहताज है। एक ओर देश के अमनपसंद आमलोग जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मान की प्राप्ति के लिए आरक्षण को अचूक हथियार समझ बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर 1947 में पाकिस्तान और 1972 में बंगलादेश लेने वालों के वंशज ब्रेक के बाद भारतीय भू-भाग पर सांप्रदायिक तांडव मचा रहे हैं। और नेताओं की नीतिगत लापरवाहियों से हमारा सिविल और पुलिस प्रशासन असहाय बना रहता है।

हैरत की बात है कि कभी ये लोग दलित-मुस्लिम समीकरण तैयार करवाते हैं तो कभी मुस्लिम-ओबीसी समीकरण को फंडिंग करवाते हैं। वहीं इसी की आड़ में कुछ अभिजात्य मुसलमान विदेशों से हवाला के जरिए फंडिंग लेकर देश में पाकिस्तान-बंगलादेश के ही नहीं बल्कि अरब देशों के हमदर्द पैदा करते हैं। इनकी नापाक मंशा जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे हालत पूरे देश में पैदा करने की है, जिसकी झलक गाहे-बगाहे दिखाते रहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी शायद यह समझ गई हैं कि इस तरह बहुत दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता।

यही कारण हैं कि दक्षिण कोलकाता के कालीघाट के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धर्म का मतलब है भक्ति, स्नेह, मानवता, शांति, सौहार्द, संस्कृति, सद्भाव और एकता है। इंसानों से प्यार करना किसी भी धर्म की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मरते हैं, तो लड़ाई क्यों? अगर हम लोगों से प्यार करते हैं तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद को अलग-थलग कर लेंगे तो हम किसी को भी नहीं जीत पाएंगे। अगर किसी पर हमला होता है, चाहे वह उपेक्षित हो, उत्पीड़ित हो, वंचित हो, हाशिए पर हो या किसी भी धर्म से हो - हम सभी के साथ खड़े हैं।

तमिलनाडु में भाजपा परचम फहराने को तत्पर

ललित गर्ग

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रही है, लेकिन अब भाजपा दक्षिण में अपनी जड़ों को न केवल मजबूत करना चाहती है बल्कि दक्षिण के राज्यों में सत्ता पर काबिज भी होना चाहती है। तमिलनाडु में अगले वर्ष अप्रैल-2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने 2026 के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को अपनी महत्वपूर्ण चैन्नई यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अहम राजनीतिक गठबंधन का ऐलान करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में एनडीए एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गठबंधन का चेहरा होंगे। तमिलनाडु की भाजपा में भी एक बड़ा बदलाव सामने आया है और भाजपा की तमिलनाडु इकाई की कमान नैनार नागेंद्रन को मिल गई है। भाजपा की राजनीतिक यात्रा में 2026 का तमिलनाडु चुनाव मील का पत्थर साबित होगा, वर्षों की प्यास को बुझायेगा, कमल खिलायेगा।

यह बात तो जगजाहिर है कि दक्षिण में हिन्दू मन्दिरों एवं संस्कृति का वर्चस्व होते हुए भी भाजपा अब तक अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाई है, जबकि केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु हो, भाजपा अपनी जड़ों को सुदृढ़ करने की जद्दोजहद करती रही है। भाजपा के प्रयास दक्षिण में बेअसर ही रहे हो, ऐसी बात भी नहीं है, समय-समय पर उसके प्रयास रंग लाते रहे हैं। दक्षिण के चार में से तीन राज्यों में भाजपा अपना प्रभाव और प्रभुत्व दिखा चुकी है। कर्नाटक में कई बार भाजपा सत्ता आसीन हो चुकी है, आंध्र प्रदेश में इस समय सत्ता की भागीदार है, तेलंगाना में भी भाजपा मजबूत पकड़ बना चुकी है, केवल तमिलनाडु ही है जहां भाजपा कई दशकों से उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद सत्ता तक नहीं पहुंच पायी है। मोदी के प्रभाव और भाजपा के विशाल संसाधनों के बावजूद तमिलनाडू जीतना उसके लिए मुश्किल रहा है। पिछले 78 सालों में यहां कभी भी भाजपा-संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा या हिंदुत्व के उनके संस्करण को स्वीकार नहीं किया है। यह सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है। लेकिन इस बार भाजपा की रणनीति एवं तैयारियों एवं मोदी-शाह के संकल्पों एवं इरादों में दम है, तमिलनाडु में आमूल-चूल परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में भाजपा की राजनीतिक रणनीति में किये गये बदलाव एवं रणनीतियां एक बड़ा मोड़ है, एक नया उजाला है। राजनीति के चाणक्य अमित शाह का यह भरोसा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा और राज्य में सरकार बनाएगा, कोरी हवा में उछाली गयी बात नहीं है।

एआईडीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन 1998 से बनते-बिगड़ते रहे हैं। 1998 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने और फिर 13 महीने बाद उसे गिराने का श्रेय भी एआईडीएमके को जाता है। जे. जयललिता का जब तक जीवनकाल रहा तब तक भाजपा नेतृत्व के साथ एआईडीएमके की नजदीकियां बनी रही। जब 1999 में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो करुणानिधि ने डीएमके को भाजपा के साथ जोड़ लिया और 2004 तक सत्ता का सुख लेते रहे। 2004 के आम चुनाव में फिर से एआईडीएमके भाजपा के साथ आई लेकिन तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें नहीं जीत सकी। लेकिन मोदी-शाह की नजरें हमेशा इस राज्य पर लगी रही। क्योंकि सामरिक रूप से तमिलनाडु एक संवेदनशील राज्य है, श्रीलंका के साथ उसका सीधा जुड़ाव है। चीन श्रीलंका के माध्यम से भारत में पैठ बनाना चाहता है, ऐसे में तमिलनाडु में केंद्र की आंख बंद कर विरोध करने वाली पार्टी का सत्तासीन रहना देश हित के लिए गंभीर सवाल पैदा करता है, अनेक संकटों का कारण बन सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपने तीसरे कार्यकाल की बड़ी चुनौतियों में बंगाल, तमिलनाडु, केरल को जीतना है। वैसे इन राज्यों में भाजपा की जीत एक करिश्मा ही होगा, लेकिन मोदी-शाह ऐसे आश्चर्यकारी करिश्में घटित करते रहे हैं। सर्वविदित है कि भाजपा के लिए तमिलनाडु केवल राजनीतिक संघर्ष का मैदान नहीं है, वैचारिक लड़ाई भी लड़ी जानी है। स्टालिन सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विवादित करने और त्रिभाषा सिद्धांत को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में प्रचारित करने से केंद्र आहत है, इसीलिये भाजपा अपने राजनीतिक सिद्धांतों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को गंभीर चुनौती दे रहे इन नेताओं और दलों को वैचारिक धरातल पर परास्त करने का रास्ता भी खोज रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्राओं एवं अन्य चर्चाओं में यह बताते रहे हैं कि पूरे तमिलनाडु की जनता एवं राज्य उनके दिल में हैं, वे उसके कल्याण एवं विकास के लिये तत्पर है। तमिल लोगों के दिलों को जीतने का काम अकेले भाजपा के द्वारा संभव नहीं है, इसीलिये एआईडीएमके की बैशाखियां उसके लिये जरूरी है।

भाजपा के राजनीतिक समीकरणों की सार्थक निष्पत्ति का एक हिस्सा है एआईडीएमके और भाजपा के ताजा गठबंधन की घोषणा। इस गठबंधन को सहज बनाने और पार्टी के अनुरूप इसका स्वरूप देने का श्रेय गृहमंत्री अमित शाह को जाता है, क्योंकि इस बार यह काम उतना आसान नहीं था। शाह एक कद्दावर नेता होने के साथ राजनीतिक गणित को समझने में माहिर है। अमित शाह जमीनी हकीकत से हमेशा वाकिफ रहते हैं। उनके पास तमिलनाडु को लेकर साफ तस्वीरें हैं, सुस्पष्ट एजेंडा है। वह एआईडीएमके के साथ अभी से उदार एवं लचीली सोच से चलना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य पता है। डीएमके एवं स्टालिन का अहंकार ही उनका मुख्य हथियार होगा। विकास के लिये सत्ता परिवर्तन जनता के लिए यदि जरूरी है तो उसे हासिल करने का तरीका भला अमित शाह से ज्यादा कौन जानता होगा।

आजकल

आतंक की चुनौती से लड़ रही सेना

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए हर स्तर पर किए गए उपायों के बावजूद आज भी वहां आए दिन जिस तरह के आतंकी घुसपैठ और हमले होते हैं, उससे यही लगता है कि वहां इस समस्या की जड़ें गहरी बनी हुई हैं। वरना क्या वजह है कि हर कुछ दिनों बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती रहती है और उसमें कभी कुछ आतंकी मारे जाते हैं, तो कई बार हमारे जवान भी शहीद हो जाते हैं। मगर इस स्थिति में एक तरह की निरंतरता बनी हुई है, जिसकी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है।

गौरतलब है कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। मगर सतर्क जवानों ने शुक्रवार देर रात केरी भट्टल इलाके में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह को देखा और उन्हें चुनौती दी। इसके बाद आतंकियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की भारत में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी, लेकिन यह दुख की बात है कि इस मुठभेड़ में भारतीय सुरक्षा बलों के एक सूबेदार घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

विडंबना यह है कि जम्मू-कश्मीर में तमाम सख्ती के बावजूद पिछले कुछ समय से एक बार फिर आतंकवाद एक जटिल रूप में उभर रहा है। हर कुछ दिनों बाद आतंकी कभी राज्य के अलग-अलग इलाकों में आम नागरिकों से लेकर सुरक्षा बलों की शिविरों तक पर हमले करते हैं, तो कभी सीमा पार के इलाकों से भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं। बाहरी प्रदेशों से आकर वहां गुजारा करने वाले प्रवासी मजदूरों और अन्य स्थानीय लोगों पर लक्षित हमले करना भी आतंकियों की एक नई रणनीति है।

शनिवार को यह खबर आई कि किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए एक अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। इस तरह की हर घटना के बाद क्षेत्र से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया जाता है, मगर यह भी सच है कि पिछले काफी समय से इस तरह के संकल्पों और उपायों के बाद भी हालत यह है कि सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों से होता है।

मुख्य मुकाबले में बने रहने को कांग्रेसी विचार मंथन...

के.एस. तोमर

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हाल ही में अपना एआईसीसी सत्र अहमदाबाद में आयोजित किया। यह फैसला केवल संयोग नहीं था, बल्कि एक सूक्ष्म राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। कांग्रेस ने ने सरदार पटेल की कर्मभूमि के भाजपा द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों के 'अधिग्रहण' को चुनौती दी और पार्टी कैडर को आगामी चुनावी संघर्षों के लिए तैयार करने का प्रयास किया।

कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि सरदार पटेल कांग्रेस के विचारों से बाहर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के प्रमुख स्थापक रहे हैं। यद्यपि एआईसीसी सत्र में नयापन और जोश नजर आया, लेकिन पार्टी के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में राज्यों में कांग्रेस की राज्यस्तरीय संगठनात्मक संरचना का कमजोर होना व युवाओं से जुड़ाव की कमी है। दरअसल, पहली बार वोट देने वाले युवा अब भी बीजेपी की राष्ट्रवाद और आकांक्षी राजनीति से अधिक प्रभावित हैं। चुनौती यह भी कि पार्टी में राहुल गांधी की औपचारिक स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। वहीं पार्टी अब तक इंडिया गठबंधन में शामिल तृणमूल, आप और सपा जैसे दलों के साथ मतभेदों का समुचित प्रबंधन नहीं कर पायी है। वहीं पार्टी भाजपा के हिन्दुत्व के ध्रुवीकरण के मुकाबले उदार हिंदू वोटर को आकर्षित नहीं कर पायी, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा-विश्वास सुनिश्चित हो।

एआईसीसी सत्र में कांग्रेस ने बूथ-स्तर के अभियानों, भारत जोड़ो यात्रा 2.0, और युवा, ऊर्जावान सोशल मीडिया पहलों की घोषणा की। कांग्रेस का 'हाथ से हाथ जोड़ो' अभियान सीधे मतदाता से संपर्क साधने का प्रयास है। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे फ्रंटल संगठनों को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है। गुजरात में कांग्रेस ने अपनी अलग पहचान को सामने रखा, मगर यह सत्र इंडिया गठबंधन में उसकी भूमिका को अनदेखा नहीं कर सका। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन को एक सूत्र में पिरोने वाली कड़ी है और सीट बंटवारे को लेकर सम्मानजनक संवाद आवश्यक होगा।

कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह गठबंधन राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु किसी भी स्थिति में दूसरे दर्जे की भूमिका स्वीकार नहीं करेगी। विशेष रूप से राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहां उसकी मजबूत पकड़ है, वह अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का यह दृष्टिकोण—स्वतंत्र शक्ति के प्रदर्शन और साझा विपक्ष की एकता बनाए रखना—2029 के आम चुनाव तक संतुलन साधने की एक बड़ी परीक्षा होगा।

पिछले दो दशकों से भाजपा के गढ़ रहे गुजरात में एआईसीसी सत्र आयोजित करना कांग्रेस का साहसिक निर्णय था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 17 सीटें जीत पाई थी। इस सत्र के जरिए पार्टी ने संकेत दिया कि वह वैचारिक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं और उन क्षेत्रों में भी फिर से जड़ें जमाएगी।

यह केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि विरासत की बात थी। कांग्रेस से जुड़े महात्मा गांधी और सरदार पटेल—दोनों महान स्वतंत्रता सेनानी—गुजरात से थे। पिछले एक दशक में भाजपा ने पटेल की छवि को हथियाने का भरपूर प्रयास किया है—उन्हें एक 'नजरअंदाज किए गए राष्ट्रवादी' के तौर पर पेश किया गया। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' इसका प्रतीक है, मगर ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि पटेल कांग्रेस के एक कट्टर नेता थे, नेहरू के घनिष्ठ सहयोगी और संवैधानिक लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर।

राहुल गांधी ने याद दिलाया कि बतौर भारत के पहले गृहमंत्री, पटेल ने रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी—एक सेक्युलर और एकजुट भारत के निर्माणकर्ता के रूप में, न कि किसी हिन्दू राष्ट्रवादी के रूप में।

संघ परिवार ने पटेल को नेहरू के वैचारिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश करने की जो कोशिश की है, उसे कांग्रेस ने तथ्यात्मक रूप से चुनौती दी। पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया और भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आयोजन के जरिये मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता ने पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन को दर्शाया, वहीं राहुल और प्रियंका गांधी ने नई पीढ़ी का चेहरा पेश किया। सोनिया गांधी ने अपने संक्षिप्त भाषण में 'सत्य और धैर्य से संघर्ष' का संकल्प दोहराया। राहुल गांधी ने मुख्य भाषण में भावनात्मक और रणनीतिक दोनों ही पक्षों को जोड़ा। उन्होंने मोदी सरकार पर संस्थाओं के दुरुपयोग, लोकतंत्र की कमजोर पड़ती संरचना, बेरोजगारी, पूंजीवाद और असहमति की आवाज को दबाने जैसे मुद्दों को उठाया।

निःसंदेह, एआईसीसी सत्र केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक पुनर्संरेखन था। सरदार पटेल की भूमि को चुनकर कांग्रेस ने भाजपा के 'राष्ट्रवाद के एकमात्र ठेकेदार' होने के दावे को खुली चुनौती दी। अब कांग्रेस एक चौराहे पर खड़ी है—या तो इस जोश को जमीनी मेहनत में बदलकर वापसी का रास्ता बनाए, या फिर मोदी की चुनावी रणनीति के सामने धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो जाए। एआईसीसी सत्र शुरुआत थी—मगर असली लड़ाई भारत के मतदाताओं के दिलों में लड़ी जाएगी।